



लोगों को रोजगार बचाने की फिक्र

यह सलाह ऐसे समय आई है जब जी-20 देशों के शिखर सम्मेलन की तैयारियां चल रही हैं। यह सम्मेलन 21 और 22 नवंबर को सऊदी अरब की राजधानी रियाध में होने वाला है। आईएमएफ ने ठीक ही कहा है कि यह समय वित्तीय घाटे की चिंता को सबसे ऊपर रखने का नहीं है।

राधा जोशी।।

आईएमएफ ने जी-20 देशों को आगाह किया है कि कोरोना वायरस का संकट अभी समाप्त नहीं हुआ है, लिहाजा सरकारों को अपनी तरफ से किए जा रहे खर्चों में कमी लाने के बजाय उन्हें और बढ़ाकर लोगों का रोजगार बचाने की फिक्र करनी चाहिए। आईएमएफ के वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से यह सामयिक सलाह सोमवार को प्रकाशित एक ब्लॉग के रूप में आई, जिसका शीर्षक था- 'संकट समाप्त नहीं हुआ है, (समझदारी से) खर्च करना जारी रखें'। यह सलाह ऐसे समय आई है जब जी-20 देशों के शिखर सम्मेलन की तैयारियां चल रही हैं। यह सम्मेलन 21 और 22 नवंबर को सऊदी अरब की राजधानी रियाध में होने वाला है।

जी-20 आज की तारीख में सही

मायनों में पूरी दुनिया की नुमाइंदगी करने वाला सबसे ताकतवर ग्लोबल आर्थिक मंच है। 19 देशों और यूरोपीय यूनियन की सदस्यता वाले इस ग्रुप के देश संसार की दो तिहाई आबादी, 80 फीसदी व्यापार और 90 फीसदी जीडीपी को कवर करते हैं। साफ है कि कोरोना जैसी वैश्विक चुनौती का सामना करने की किसी भी साझा रणनीति पर विचार करने और उसे अमल में लाने का इससे बेहतर कोई मंच नहीं हो सकता।

महामारी और खासकर उससे उपजी आर्थिक चुनौतियों का सामना करने का जो मिला-जुला प्रयास अब तक दिखा है उसमें भी जी-20 की अहम भूमिका रही है। आईएमएफ के इस ब्लॉग में यह बात रेखांकित की गई है कि जी-20 देशों की

अभूतपूर्व और त्वरित कार्रवाई ने संकट को और गहरा होने से रोका। इस संकट से निपटने की कोशिशों में वे अबतक 11 लाख करोड़ डॉलर झोंक चुके हैं। स्वाभाविक है कि इन देशों को भी अब अपने संसाधन कम पड़ते हुए लग रहे हैं। वित्तीय घाटे को एक सीमा से आगे न जाने देने का दबाव सारी ही सरकारों के हाथ बांध रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कोरोना वायरस अभी तक काबू

में आने का कोई संकेत नहीं दे रहा है। जिन देशों में प्रतिदिन आने वाले नए केंसों की संख्या काफी कम हो गई थी, वहां भी इसकी दूसरी लहर आने की खबर है। जाहिर है, फैक्ट्रियों की मशीनें पुरानी

रफतार से चलने और काम-धंधों के पटरी पर लौटने की उम्मीद अगले दो-चार महीनों में नहीं की जा सकती। ऐसे में सबसे जरूरी बात यह है कि सरकारें समाज के कमजोर हिस्सों की जेब में पैसा पहुंचाते हुए जिंदा रहने की जद्दोजहद में उनकी मदद करें और छोटे कारोबारियों तथा कंपनियों की सहायता करके लोगों का रोजगार बचाने की कोशिश जारी रखें।

आईएमएफ ने ठीक ही कहा है कि यह समय वित्तीय घाटे की चिंता को सबसे ऊपर रखने का नहीं है। उम्मीद की जाए कि सही समय पर आई इस सलाह की रोशनी में जी-20 देश दुनिया की साझा आर्थिक चुनौतियों से निपटने की उपयुक्त और एकीकृत रणनीति तैयार कर सकेंगे।



विचार करें

अशोक वोहरा।

जो श्रीराम जन्म से शुद्ध महर्षि वाल्मीकि के सामने सर नवाते हों, जो श्रीराम निषादराज गुह को अपने चरणों से उठा कर

अपने हृदय से लगाते हों, जो श्रीराम वानरों और रीछों के समुदाय को अपने समकक्ष बिठाते हों, जो श्रीराम एक राक्षस विभीषण को भी शरण देते हों, जो श्रीराम एक भीलनी शबरी के जूटे बेर तक प्रेम पूर्वक खा लेते हों, क्या आपको लगता है कि वही श्रीराम एक शुद्ध को केवल इसलिए मार देंगे क्योंकि वो वेदपाठी था? कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। इस तर्क के आधार पर तो उन्हें महर्षि वाल्मीकि को भी मार देना चाहिए था। रामायण में एक प्रसंग है कि जब मंधरा ने सीता माँ को वल्कल वस्त्र दिए तो उन्हें उसे पहनना नहीं आया। तब श्रीराम स्वयं अपने हाथों से वो वल्कल वस्त्र अपनी पत्नी को पहनाते हैं।

धर्म-दर्शन



संपादकीय

बाधाएं थीं रास्ते में

एक बड़ी परीक्षा से अभी गुजरना बाकी था। लोकसभा चुनाव के बाद वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने और देवीलाल उप प्रधानमंत्री। इस बीच बहुगुणा की हृदय चिकित्सा के दौरान मृत्यु हो गई। चंद्रशेखर इस बीच वीपी सिंह के विरुद्ध काफी मुखर हो चुके थे। समूची पार्टी में संदेह एवं अविश्वास का वातावरण था। इसी माहौल में 1990 में बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई। नीतीश कुमार ने केंद्र में राज्यमंत्री पद स्वीकार कर लालू प्रसाद के लिए पहले ही रास्ता साफ कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद चुनाव के बाद जनता दल विधानमंडल के नेता पद को लेकर घमासान शुरू हो गया। जनता दल विधानसभा में 122 सीट जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरा। अब मुख्यमंत्री पद के लिए देवीलाल खेमे से लालू प्रसाद और वीपी सिंह खेमे से रामसुंदर दास आमने-सामने थे। जॉर्ज फर्नांडिस और चौधरी अजीत सिंह का भी इन्हें समर्थन प्राप्त था। चंद्रशेखर ने भी अपने विश्वासी रघुनाथ झा को उम्मीदवार बनाया। थोड़े अंतर से लालू प्रसाद चुनाव जीत गए, जिसमें निस्संदेह नीतीश कुमार के संचालन की महती भूमिका थी। मगर राज्यपाल यूनूस सलीम ने लालू प्रसाद को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने में 1 सप्ताह से अधिक का समय लगा दिया। जब देवीलाल खेमे ने राजभवन को घेरने की धमकी दी, उसके बाद ही 10 मार्च 1990 को शपथ ग्रहण को संभव हुआ।

इस रूपरेखा को अमली जामा पहनाने के लिए चौधरी देवीलाल दिन-रात एक किए हुए थे, लेकिन लोकदल और जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व वीपी सिंह के नाम पर बंटता हुआ था।

कर्पूरी और देवीलाल की दोस्ती

केसी त्यागी।।

वीपी सिंह की भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम अपने चरम पर थी। लाखों की संख्या में लोग उन्हें सुनने के लिए एकत्रित हो रहे थे। भारतीय जनता पार्टी और वामदल भी इस मुहिम को अपना समर्थन देकर इसे और व्यापक रूप दे चुके थे। गैर बीजेपी दलों पर दबाव बनने लगा कि वीपी सिंह के नेतृत्व में नए दल का गठन हो। इस रूपरेखा को अमली जामा पहनाने के लिए चौधरी देवीलाल दिन-रात एक किए हुए थे, लेकिन लोकदल और जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व वीपी सिंह के नाम पर बंटता हुआ था।

चरण सिंह की मृत्यु के बाद दल के कार्यकारी अध्यक्ष हेमवती नंदन बहुगुणा खुले तौर पर चौधरी देवीलाल की मुहिम को पटखनी देने में लगे हुए थे। उत्तर प्रदेश के बड़े नेता मुलायम सिंह यादव स्थानीय कारणों से वीपी सिंह से खफा थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए मुलायम सिंह यादव उनके निशाने पर रहे थे। जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता चंद्रशेखर भी वीपी सिंह के कटु आलोचक थे, लेकिन उनकी पार्टी के लगभग सभी बड़े नेता उनसे भिन्न राय रखते हुए वीपी सिंह के नेतृत्व में नए दल के निर्माण की मुहिम को समर्थन दे रहे थे। रामकृष्ण हेगड़े, मधु दंडवते, सुरेंद्र मोहन, जयपाल रेड्डी सार्वजनिक



तौर पर चंद्रशेखर की आलोचना कर चुके थे।

सभी की नजरें बिहार में कर्पूरी ठाकुर पर टिकी थीं। वे पिछड़ों के सबसे असरदार नेता के रूप में स्थापित हो चुके थे। लिहाजा उनका रुख काफी निर्णायक था। चौधरी देवीलाल और कर्पूरी ठाकुर की मित्रता जगजाहिर थी। जब 1982 में चौधरी चरण सिंह द्वारा देवीलाल को लोकदल से निष्कासित किया गया तो इसका विरोध करने वालों में वे सबसे आगे थे। बाद में लोकदल (कर्पूरी) का गठन हुआ। सभी बड़े नेता उसमें शामिल हुए। लोकदल (क) बाद में जनता पार्टी में शामिल हो गया। कर्पूरी ठाकुर और देवीलाल उस

दांचे में स्वयं को असहज महसूस करने लगे। जिन नेताओं के कारण उनका मुख्यमंत्री पद गया, जनता पार्टी में वे नेता महत्वपूर्ण पदों पर आसीन थे। लिहाजा दोनों नेता 1984 में चरण सिंह द्वारा बनाई पार्टी डीएमकेपी में शामिल हो गए और जीवन पर्यंत दोनों साथ बने रहे।

17 फरवरी 1988 को दिल का दौरा पड़ने के बाद कर्पूरी ठाकुर का देहांत हो गया। उनकी शव यात्रा में गरीब लोगों की उमड़ी भीड़ उनकी लोकप्रियता का प्रमाण दे रही थी। लोकदल के लगभग सभी नेता इस अवसर पर शोकाकुल भी थे और आशंकित भी। उनके राजनीतिक कद के आसपास का कोई नेता बिहार पार्टी में नहीं था। देवीलाल व बहुगुणा दोनों खेमों में कर्पूरी के बाद की राजनीति को लेकर खींचतान तेज हो गई। लंबे समय से यादव समुदाय के लोग अपने नेतृत्व को स्थापित कराने का मंसूबा बनाए बैठे थे। चूँकि संख्या बल के मुताबिक पिछड़ी जातियों में सबसे अधिक वही थे और डेढ़ दर्जन विधायक भी इसी वर्ग से चुने गए थे, लिहाजा एक आम सहमति तैयार हो रही थी कि किसी यादव को ही यह पद सौंपा जाए। संख्या के मुताबिक विधानसभा में लगभग 45 विधायक लोकदल के थे। यानी स्पष्ट था कि लोकदल का चुनाव गया नेता ही प्रतिपक्ष का नेता होगा और विधानसभा चुनाव के बाद संख्या बल के आधार पर उसे ही मुख्यमंत्री पद मिलेगा।

सूडोकू नवताल-5402

9		6		
4	7		8	3
	8	7	3	1
8	9		5	1
				7
5	1		8	7
	2	4		6
7	1	3		5
			1	
				4

सूडोकू नवताल-5401 का हल

1	9	3	7	5	4	2	6	8
8	4	2	1	6	3	9	7	5
5	7	6	8	2	9	3	1	4
3	1	5	6	3	2	8	9	7
7	2	9	4	8	1	6	5	3
3	6	8	5	9	7	1	4	2
2	5	1	9	4	8	7	3	6
9	8	4	3	7	6	5	2	1
6	3	7	2	1	5	4	8	9

अपना ब्लॉग जिम्मेदारी के लिए चुना

मोहन। बहुगुणा खेमे में कई बड़े कदावर यादव विधायक थे, जिनमें विनायक प्रसाद, गजेंद्र हिमांशु और अनूप लाल यादव शामिल थे। देवीलाल के पास कोई नामधारी यादव नहीं था, जिसे इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए चुना जा सके। लोकदल के गैर यादव पिछड़ी जाति के विधायकों में नीतीश कुमार काफी सक्रिय थे। चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में वे राष्ट्रीय स्तर पर युवा संगठन में पदाधिकारी रह चुके थे और कर्पूरी ठाकुर के साथ बिहार के पार्टी युवा संगठन के अध्यक्ष भी। शरद यादव, चौधरी देवीलाल के प्रतिनिधि के रूप में डेरा डाले हुए थे। अंत में सर्वसम्मति से तय हुआ कि यादव समूह के विधायकों में जिसकी संख्या अधिक होगी, उसे ही जिम्मेदारी मिलेगी। पटना में मीटिंग की तिथि तय हो गई। नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद का नाम सुझाया, तो एक झटके में सभी आश्चर्यचकित थे। शुरू में शरद यादव को भी उनके नाम पर सहमति बनाने में परेशानी हुई।

नेपोटिजम...

